सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-33
17/01/2018

सामाजिक चेतना के बिना हमें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलेगी :– मुख्यमंत्री

पटना, 17 जनवरी 2018 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड के ग्राम हांसीबेगमपुर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने सात निश्चय एवं विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल मंच से 438.15 करोड़ रुपये की लागत वाली 219 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर किया। गाँव भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या– 50 से महादलित टोला होते हुए, मुख्य सड़क तक निर्मित इंटरलॉकिंग पथ का उद्घाटन किया। हांसीबेगमपुर के वार्ड संख्या 6 के महादलित टोला में बने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या– 50 का उद्घाटन शिलापट्ट का अनावरण और रिबन काटकर मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने यहॉ पर वृक्षारोपण भी किया। विकास योजनाओं की सतही हकीकत का निरीक्षण करने के क्रम में मुख्यमंत्री ने सुमित्रा देवी, मंजुला देवी, नीरो देवी, विनोद ऋषि, रीना देवी जैसे अन्य कई ग्रामीणों के दरवाजे पर जाकर बिजली, पानी, शौचालय निर्माण के साथ ही 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की पूरी जानकारी ली। गॉव भ्रमण के बाद जनसभा स्थल मंच पर मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी ने पुष्प–गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूलों की बड़ी माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभुकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने चार महिलाओं को स्वरोजगार के लिये चेक भी प्रदान किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी अधिक ठंड में काफी संख्या में आप सब इस कार्यक्रम में मौजूद हुये हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में हमने तय किया कि वर्ष 2009 में विकास यात्रा के क्रम में हम जिन जिलों के जिन–जिन स्थान पर गए थे और रात में अपने अधिकारीगण और मंत्रीगण के साथ टेंट में रुके थे, उन जगहों पर इस बार समीक्षा यात्रा में हम जरुर जाएंगे। इसी सिलसिले में हांसीबेगमपुर का कार्यक्रम तय हुआ, जहां हम 12 फरवरी 2009 को आए थे और रात में रुके थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 में विकास यात्रा के दौरान हांसीबेगमपुर में लोगों से संवाद हुआ था और यहां जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें हुईं और लोगों की मांग पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया, जिसको देखते हुए हमने काफी कोशिश की कि जो मांगें लोगों द्वारा उस समय उठाई गई थी, वह जल्द से जल्द पूरा हो सके। इस कड़ी में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय वर्ष 2010 से ही संचालित है, जिसकी घोषणा उस समय लोगों की मांग पर हमने की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा के दौरान लोगों ने पूर्णिया को नगर निगम बनाने की मांग की थी, जो अब नगर निगम बन गया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त 30 मेगावाट नियमित रूप से पूर्णिया में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर लोगों ने आवाज उठाई थी और आज 75 से 80 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों

में काम हो रहा है, वह चाहे बुनियादी ढांचा हो, पुल–पुलिया, कृषि क्षेत्र का विकास, कल्याण का काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सब पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं के जरिए भी हमने लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम और स्वयं सहायता भत्ता के जरिए युवाओं को सबल बनाने की हमने कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जी0एन0एम0 संस्थान, पारा मेडिकल संस्थान खोले जा रहे हैं, जबकि हर सब डिवीजन में महिला आई0टी0आई0 और ए0एन0एम0 स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए जमीन और धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है ताकि बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ए0एन0एम0 स्कूल जी0एन0एम0 संस्थान और सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है ताकि भारी संख्या में महिलाएं नर्स का प्रशिक्षण ले सकें। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नर्सेज की भारी कमी है, जिसको देखते हुए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है ताकि बिहार में जो नर्सों की कमी है, उसे पूरा किया जाए। साथ ही नर्स की प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को बिहार के बाहर भी रोजगार मिल सके।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया, वहीं लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की गयी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक आठ लाख स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है और हमारा लक्ष्य इसे दस लाख करने का है। इससे एक से डेढ़ करोड़ महिलाएं जुड़ेंगी और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी और पुलिस बहाली में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पद पर महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही थानों में महिलाओं के लिए शौचालय और वाशरूम की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल, हर घर शौचालय का निर्माण, हर घर पक्की गली–नाली के साथ ही हर घर बिजली कनेक्शन मुहैया कराने का हमारा लक्ष्य है, जिसे 4 साल के अंदर हर हाल में लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हो रहा है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। इसके लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत भी काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है और जो कुछ टोलें बचे हैं, उनमें अप्रैल महीने तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, जबकि पूरे बिहार में जो इच्छुक परिवार हैं, उन तक इस साल के अंत तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि लोगों को अगर पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए और खुले में शौच से छुटकारा मिल जाए तो 90 प्रतिशत बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां पानी गुणवत्ता प्रभावित है, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की समस्या है, वहां लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से जबकि जहां गुणवत्ता की समस्या नहीं है, वहां पंचायतों के माध्यम से वार्डवार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के कामों को देखने हम गांव में निकले हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल और हर घर पक्की गली–नाली का निर्माण पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसको लेकर बीच के दिनों में मुखिया जी कुछ लोगों के बहकावे में आ गए थे, जिसके कारण काम में बाधा उत्पन्न हुई लेकिन अब वार्ड मेंबर हों या मुखिया जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्हें अब यह बात समझ में आ गई है कि अगर उनके पंचायत में काम होगा तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग उनकी तारीफ करेंगे न की शिकायत। मुख्यमंत्री ने

कहा कि निश्चय योजनाओं से लोगों को काफी फायदा होने वाला है लेकिन इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की छवि बदल जाएगी, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 438.15 करोड़ रुपए की लागत से 219 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा।

शराबबंदी की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर ही पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसका फायदा लोगों को काफी मिल रहा है। शराबबंदी के बाद पूरे बिहार में शांति और सद्भाव का माहौल है। पहले लोग जहां शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे, अब उन घरों में शांति है। शराब सेवन में अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा जो लोग गंवा देते थे उन पैसों का इस्तेमाल परिवार के भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है।

पूर्णिया जिला प्रशासन द्वारा 'परिवर्तन' पुस्तिका प्रकाशित किए जाने पर प्रशंसा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के बाद बेरोजगार हुए लोगों को पूर्णिया जिला प्रशासन ने जिस तरह से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था 2–2 गाय उपलब्ध कराकर या अन्य कई चीजों को अपनाकर किया है, हम चाहते हैं के पूरे बिहार में इसी के अनुरूप काम हो ताकि शराबबंदी से बेरोजगार हुए लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद भी सरकारी तंत्र के लोगों के साथ मिल–जुलकर के कुछ दो नंबरी लोग अब भी शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस महानिरिक्षक मद्य निषेध का तंत्र भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में जो बिजली के ट्रांसफार्मर के खंभे लगे हैं, उन पर पुलिस विभाग और मद्य निषेध विभाग का टेलीफोन नंबर लिखा गया है, जिसे कुछ दिन बाद हटा कर उन खंभों पर एक नंबर लिखा जाएगा, जिस पर आप फोन करके शराब का अवैध कारोबार करने या शराब का सेवन करने वाले लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और आपकी सूचना पर घंटे भर के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वालों का नाम नाम गोपनीय रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने तंत्र को जितना संभव है, सुदृढ़ करने में लगी है लेकिन सामाजिक चेतना के बिना हमें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई है, उसका दूसरे राज्य और दूसरे देश के लोग अध्ययन करने बिहार आ रहे हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमलोगों ने इसे सोच समझकर लागू किया है। 21 जनवरी 2017 को शराबबंदी और नशामुक्ति के पक्ष में बनी मानव श्रृंखला का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चार करोड़ लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था, ऐसे में अब 21 जनवरी 2018 को एक बार फिर मानव श्रृंखला बनने वाली है जो दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संवाद कार्यक्रम में एक महिला आई और उसने कहा शराबबंदी करके आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन दहेज प्रथा से भी हमे छुटकारा मिलना चाहिए, जिसके बाद हमने निर्णय लिया और इसके खिलाफ सशक्त अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि लोग कम उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर बेटी बड़ी होगी तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए कानून बना हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी शादियॉ हो रही हैं। इसके लिए जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और 21 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में शादी होने से प्रसव के दौरान अधिकांश महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं या

जो बच्चे पैदा होते हैं वे कई प्रकार की बीमारियों, मंदबुद्धि, बौनेपन और मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं। पहले दहेज प्रथा सम्पन्न लोगों में थी लेकिन अब धीरे धीरे आम लोगों में फैल गई है। लोगों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जिस दिन दहेज का लेन देन करने वाले परिवारों के शादी समारोह में शामिल नहीं होने का मन बना लीजिएगा, उस दिन समाज से दहेज प्रथा का खात्मा हो जाएगा लेकिन इसमें किसी तरह का अपवाद नहीं होना चाहिए नहीं तो नतीजा नहीं निकलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका असर तुरंत देखने को मिलेगा क्योंकि दहेज लेने वाला अलग–थलग पड़ जाएगा और भांडा फूटने के डर से वह दहेज नहीं लेगा। अपराध के आकड़ों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार 22वें स्थान पर है, जबकि दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में बिहार की बहुत ही खराब स्थिति है। यू0पी0 के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है जो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा और बाल विवाह से मुक्ति पाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। जनसभा में मौजूद लोगों को हाथ उठाकर मानव श्रृंखला में शामिल होने का संकल्प दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यास्त के समय आप सबने हाथ उठाकर मानव श्रृंखला में शामिल होने का संकल्प लिया है इसलिए 21 जनवरी को उस दिन रविवार का दिन है, आप सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला में जरूर शामिल होइएगा और अपनी भावना का प्रकटीकरण कीजिएगा ताकि बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन अभियान को बल मिल सके।

जनसभा को जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कला संस्कृति मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर सांसद श्री संतोष कुशवाहा, विधायक श्रीमती लेसी सिंह, विधायक श्रीमती बीमा भारती, विधायक श्री विजय खेमका, विधान पार्षद श्री दिलीप जायसवाल, पूर्व मंत्री श्री दुलाल चंद गोस्वामी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल रंजन वर्मा, लोजपा जिलाध्यक्ष श्री माधव सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत, पूर्णिया कमिश्नर सुश्री टी0एन0 विन्देश्वरी, जिलाधिकारी श्री प्रदीप कुमार झा, पुलिस अधीक्षक श्री निशांत तिवारी सहित अन्य वरीय अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित थे।

******